

उत्कर्ष योजना के तहत 6वीं में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित
महासमूंद। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग आयुक्त के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विधायी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
कलेक्टर ने पद्मश्री दम्पति डा. गोडबोले का किया सम्मान



रायपुर। पद्मश्री दम्पति डाक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले से शुक्रवार को कलेक्टर गौरव सिंह ने मुलाकात की। कलेक्टर ने उनका शॉल, पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मान किया। साथ ही शुभकामनाएं दी और कहा कि आप लोग हमारे प्रदेश के गौरव है।गौरवलब है कि गत दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री दम्पति डॉ रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़कर अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बस्तर के बारसूर जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम वनांचल में रहकर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोगों तक निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता और जनविश्वास का प्रकाश पहुँचाया।

वार्ड 26 में विकास कार्यों की सौगात

रायपुर। राजधानी रायपुर के जोन 2 अंतर्गत दानवौर भामाशाह वार्ड क्रमांक-26 में शुक्रवार को कई विकास कार्यों की सौगात दी गई। इसके तहत लगभग 50 लाख रुपए के स्वीकृत नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, साथ ही लगभग 75 लाख के नए विकास कार्य पूर्ण होने पर उनका लोकार्पण किया। महापौर मीनल चौबे, विधायक राजेश मृण्त, सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने स्वीकृत विकास कार्य के लिए पूजा और कुदाल चलाकर भूमिपूजन किया। इस अवसर पर लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, जोन अध्यक्ष गज्जू साहू, दानवौर भामाशाह वार्ड पार्षद रामहीन कुरें सहित बड़ी संख्या अन्य लोग उपस्थित रहे।

हांडी तालाब की कराई गई सफाई



रायपुर। शहर के तात्यापारा वार्ड क्षेत्र में हांडी तालाब गंदगी एवं जलकुंभी से पट चुका है। नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को इस तालाब में सफाई अभियान चलाया। जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू की मौजूदगी में लगभग 15 सफाई कामगारों की विशेष टीम के जरिए हांडी तालाब में फैली जलकुम्भी को बाहर निकालने का कार्य किया।

85 हजार शिक्षकों को दिलाना होगा टेट, कर्मचारी चयन बोर्ड के स्थान पर विभागीय परीक्षा की तैयारी

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

प्रदेश के 85 हजार शिक्षकों को वेतनवृद्धि अथवा पदोन्नति के लिए टेट दिलानी होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देते हुए सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब तक व्यापम शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करता आ रहा है।

व्यापम का स्थान अब कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। भविष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, लेकिन कार्यरत शिक्षकों के लिए परीक्षा विभागीय स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। इसके पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 13 मार्च 2026 को सभी संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों से उन शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 85 हजार है। टेट अनिवार्य

मौसम ने उतारी बिजली की गर्मी, खपत डेढ़ हजार मेगावाट तक घटी

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

प्रदेश में वैसे तो भीषण गर्मी पड़ रही है और नैतपा भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हो रही है, तो कहीं ओले भी गिर रहे हैं। कहीं बादल छाए हुए हैं। ऐसे में बिजली की खपत की गर्मी भी उतर गई है। जो खपत बीते माह सात हजार मेगावाट के पार चली गई थी, वह अब छह हजार मेगावाट से भी कम हो रही है।

पीक आवर में भी खपत छह हजार मेगावाट के पार नहीं जा रही है। मई का प्रारंभ ही मौसम के बदलने से हुआ है, अब तो मई समाप्त होने को है, लेकिन अभी मौसम के कुछ दिनों तक इसी तरह से रहने की संभावना है। मौसम ऐसा ही रहा, तो यह बात तय है कि बिजली की खपत और भी कम होगी। इस समय

- अब पीक आवर में खपत छह हजार मेगावाट से कम
- अप्रैल में सात हजार मेगावाट के पार गई थी खपत



धान खरीदी केंद्रों के भौतिक सत्यापन में सामने आई गड़बड़ी

12 समितियों में 6590 कि्वंटल धान शॉर्टेज मिला, 3 के खिलाफ एफआईआर

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

रायपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव होने के बाद सभी समितियों में शेष भंडारित धान की जांच की गई। इस जांच में 12 समितियों में कुल 6590 कि्वंटल धान का शॉर्टेज पाया गया है। इसके तहत इन समितियों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से तीन समितियों का जवाब आया है, जिसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इस मामले में अब प्रशासन स्तर पर समितियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 3 समितियों के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है, वहीं अन्य समितियों के खिलाफ भी एफआईआर कराए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि धान खरीदी समिति संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने समिति प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गलत बताया है।

शॉर्टेज के बदले धान-राशि जमा करने के निर्देश

भौतिक सत्यापन के दौरान जिन धान खरीदी केंद्र समितियों में धान का शॉर्टेज मिला है, उन समितियों के प्रबंधकों को शॉर्टेज धान के बदले में धान या राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी समिति ने इसका पालन नहीं किया है। समितियों की मनमानी के चलते अब प्रशासन उनके खिलाफ एफआईआर कराने की कार्रवाई कर रही है।



फाइल फोटो

इन समितियों के खिलाफ एफआईआर
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खान धरसीवा, रवेली अमनपुर एवं छदिया खरोरा समितियों के खिलाफ थाने में एफआईआर कराई गई है। इन समितियों के प्रबंधकों ने शॉर्टेज धान की भरपाई करने से इंकार कर दिए हैं। इस कारण से उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

समितियों में 229 से 850 कि्वंटल तक धान शॉर्टेज
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उद्यमोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के धान खरीदी केंद्र समितियों में धान स्टॉक शुरू हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग ने रायपुर जिले में भी कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में खाद्य, राजस्व, मंडी एवं सहकरिता विभाग के निरीक्षकों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों की धान समितियों में जाकर भंडारित धान का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान धान समितियों में बड़ी मात्रा में धान का शॉर्टेज मिला है, जिसकी कुल क़ीमत करोड़ों रुपए में है। मिली जानकारी के अनुसार जिन समितियों में धान शॉर्टेज मिला है, उनमें कहीं 229 कि्वंटल, कहीं 5 से 6 सौ, तो कहीं 7 से साढ़े 8 सौ कि्वंटल धान शॉर्टेज मिला है। रायपुर के अलावा अन्य कई जिलों में भी कई समितियों में धान शॉर्टेज मिलने की खबर है।

पुनर्मूल्यांकन तिथि आगे बढ़ी, अब आवेदन जून में

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूेशन के लिए पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल अब 1 जून से शुरू किया जाएगा।

इससे पहले सीबीएसई ने कहा था कि आवेदन पोर्टल शुक्रवार, यानी 29 मई तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शी और बिना तकनीकी दिक्कत वाली प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल को 1 जून से चालू किया जाएगा। सीबीएसई के अनुसार, यह फैसला

अंक बढ़े तो शुल्क वापस

अगर किसी छात्र को प्रक्रिया से जुड़ा कोई सवाल या समस्या हो, तो वे सीबीएसई की टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800 11 8004 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र resultcbse2026@cbseashiksha.in ईमेल आईडी पर भी अपनी शिकायत या सवाल भेज सकते हैं। पूर्ण में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद सीबीएसई ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया था। संशोधन के मुताबिक, रैकेन कॉपी प्राप्त करने और मावर्स वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को प्रति विषय 100 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं, री-इवैल्यूेशन के लिए शुल्क प्रति प्रश्न के हिसाब से लिया जाएगा, जो कि 25 रुपए प्रति प्रश्न निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर री-इवैल्यूेशन के बाद किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं, तो उससे लिया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार समय पर परीक्षा कराना अनिवार्य
- टेट अनुत्तीर्ण शिक्षकों की पदोन्नति-वेतनवृद्धि नहीं

समय-सीमा में वृद्धि

कोर्ट ने राहत देते हुए परीक्षा पास करने की समय-सीमा को 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। लेकिन अन्य प्रावधानों में छूट नहीं दी गई है।। सेवानिवृत्ति से जुड़े निरमजिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष या उससे कम का समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है, उनके लिए टेट पास करना पूर्णतया अनिवार्य है और ऐसा न करने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

करने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 मई को दिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित राज्यों और सक्षम अधिकारियों को समय-समय पर टेट आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पचास से ज्यादा दुकानों की जांच 105 किलो सड़े आम और केले नष्ट



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने तीन दिन के भीतर राजधानी में पचास से ज्यादा फल दुकानों की जांच की। इस दौरान 105 किलो आम और सड़े केले नष्ट कराए गए। कारोबारियों को इस दौरान चेतावनी दी गई कि फलों पर स्टीकर नहीं लगाएं और उन्हें पकाने केमिकल अथवा अन्य रसायनों का इस्तेमाल ना करें।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रक दीपक अग्रवाल ने 27 से 29 मई तक जिला स्तर पर फलों की जांच के लिए अभियान चलाने का निर्देश जारी किया था। इस दौरान मिलने वाले सड़े-गले फलों को नष्ट कराने की हिदायत भी दी गई है। कलेक्टर डा. गौरव सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले की टीम ने इस अवधि में शहर की 52 फल विक्रेता फर्मों का

औफलाइन परीक्षा की मांग
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने जुलाई माह में विभागीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया है। शिक्षक संघ के अनुसार, 6 माह के अंतराल में यदि प्रत्येक वर्ष 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए तो योग्य शिक्षकों को कानूनी जल्दतर को पूरा करने का सही मौका मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने, विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा के आयोजन से न्यायालय व शासन की जटिलताएं पूरी तरह दूर हो जाएंगी। एसोसिएशन ने शासन को सुझाव दिया है कि शिक्षकों की सुविधा के लिए प्रत्येक विकासखंड की 5-7 बड़ी शालाओं या संकुल शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाए, ताकि शिक्षक अपनी निकटस्थ शाला में आसानी से परीक्षा दे सकें। परीक्षा के अंतवर्त पेपर-1 एवं पेपर-11 दोनों आयोजित किए जाएं। शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन आयोजित की जाए। चूंकि यह सेवकालीन शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा है, इसलिए न्यूनतम उत्तीर्णक निर्धारित किया जाए।

रायपुर/महासमुंद जिला हरिभूमि 11

अपना उत्पादन कम

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर के संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 2960 मेगावाट है।लेकिन कभी भी उत्पादन 26 से 27 सौ मेगावाट तक ही हो पाता है। इस समय तो अपना दो हजार मेगावाट के आस-पास हो रहा है। अब तक कोरबा वेस्ट के संयंत्र में एक 210 मेगावाट के दो संयंत्र खराब है।ये संयंत्र करीब एक माह से खराब ही पड़े हैं।खपत ज्यादा न होने के कारण इनको जल्द पराम करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।खपत की पूर्ति करने के लिए सेंट्रल सेक्टर से रोज साढ़े तीन हजार मेगावाट बिजली ले रहे हैं।इतने का प्रदेश का शेयर भी है। अप्रैल में तो सेंट्रल सेक्टर से रोज पांच हजार मेगावाट तक बिजली लेनी पड़ी थी। पॉवर कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक 210 मेगावाट के संयंत्रों को जल्द पराम कर दिया जाएगा। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर से और कम बिजली लेनी पड़ेगी।

बिजली की खपत जहां दिन के समय में 51 से 52 सौ मेगावाट हो रही है, वहीं शाम को पीक आवर में खपत छह हजार मेगावाट से कम हो रही है। जहां पर भी बारिश हो रही है, वहीं पर एसी और कूलर कम चल रहे हैं।

अप्रैल में बना खपत का रिकॉर्ड

अप्रैल में इस बार खपत का नया रिकॉर्ड बना। बीते साल गर्मी में खपत सात हजार मेगावाट के पार गई थी। लेकिन इस बार खपत 73 सौ मेगावाट के करीब पहुंच गई। अप्रैल में लगातार करीब एक सप्ताह तक खपत सात हजार मेगावाट के आस-पास रही है। पहले कभी इतनी खपत नहीं होती थी। ऐसे में लग रहा था कि मई में खपत का पारा 75 सौ मेगावाट तक जा सकता है, लेकिन मई के मौसम ने बिजली की खपत की पूरी खुमारी उतार दी है।

बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग रावाभांटा इलाके में दहशत



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

रावाभांटा स्थित भारती फूड्स फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि संबंधित अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रित है। जानकारी के अनुसार, खमतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रावाभांटा स्थित भारती फूड्स में बिस्किट का निर्माण होता है। यहां शुक्रवार देर रात एक हिस्से में आग

चार करोड़ की क्षति

नेटन पार्क स्थित यह फूड फैक्ट्री भारती कोडवानी की बताई जा रही है। फैक्ट्री में बिस्किट निर्माण होता है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आग की भीषणता को देखते हुए लगभग 4 करोड़ की क्षति का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनमें खाद्य हुई लगभग 1.5 करोड़ की मशीन शामिल है। करीब 2 करोड़ की बिस्किट खाद्य होने की भी बात कही जा रही है। मामले की जानकारी होते ही उरला थाना पुलिस समेत आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। किसी तरह की जनहानि की सूचना खबर लिखे जाने तक नहीं है।

मूल स्वरूप में विराजित हो गणेश प्रतिमाएं

हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

विश्व हिंदू परिषद जिला महासमुंद ने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, अनुविभागीय अधिकारी अक्षा गुप्ता को आगामी माह में गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजा पंडालों में विराजित श्री गणेश की प्रतिमा अपने मूल स्वरूप में विराजित करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन चंद्राकर ने बताया कि पिछले वर्ष गणेश उत्सव के दौरान कार्टून आधारित अशोभनीय प्रतिमा पूजा पंडालों पर विराजित की गई थी, जिससे हिंदुओं की आस्था एवं धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, जिसका पूरे छत्तीसगढ़ में भारी विरोध हुआ।

कुछ स्थानों पर प्रतिमा जब्त कर तत्काल विसर्जन की करवाई भी की गई। ऐसी घटना न दोहराई जाए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने समय पूर्व ही जिला कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को पत्र प्रेषित कर प्रतिमा विराजित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कने। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी।मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



समिति के सदस्यों को पूर्व से ही निवेदन किया है। भगवान गणेश के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं मूल स्वरूप से भिन्न प्रतिमा को तत्काल विसर्जित कर संबंधित गणेशोत्सव समिति एवं मूर्ति निर्माता के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस बाबत गणेशोत्सव पर्व पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी पूजा पंडालों का भ्रमण किया जाएगा एवं हिंदू धर्म संस्कृति के विधि विधान से गणेशोत्सव मनाने का आह्वान किया जाएगा।जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन चंद्राकर ने बताया कि चूंकि प्रतिमा निर्माण का

कार्य प्रारंभ हो चुका है, इसलिए बजरंग दल के सदस्यों द्वारा कुम्हारों से संपर्क कर गणेश के मूल स्वरूप में ही प्रतिमा निर्माण का निवेदन किया जा रहा है।इस दौरान जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन चंद्राकर, नगर अध्यक्ष चंद्रबदन मिश्रा, दानेश्वर सिन्हा, नगर मंत्री अश्वनी शर्मा, ग्रामीण उपाध्यक्ष उदयराम साहू, सुरेंद्र महाराज, चंदन नेताम, राहिल गुप्ता, कान्हा प्रधान, रामेश्वर पांडे, गोलू साहू, संजय यादव, प्रमोद साहू, रामेश्वर गोलू साहू सहित बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

टाउन हॉल में सेवानिवृत्त 68 कर्मचारी हुए सम्मानित

रायपुर। कलेक्टोरेट परिसर स्थित टाउन हॉल में शुक्रवार को कलेक्टर गौरव सिंह के मुख्य आतिथ्य में सम्मान समारोह हुआ। इसमें सेवानिवृत्त होने वाले 68 शासकीय कर्मचारियों को श्रीफल, शॉल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कलेक्टर ने सम्मानित किया, साथ ही सभी कर्मचारी को सभी सत्वों का तत्काल भुगतान

किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में स्कूल शिक्षा विभाग से 21, स्वास्थ्य विभाग से 3, राजस्व विभाग से 2, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से 2, जल संसाधन विभाग से 11, उच्च शिक्षा विभाग के 7, पशुधन विकास विभाग से 2, वन विभाग से 3, लोक निर्माण विभाग से 2, जेल विभाग से 3, उद्यानिकी विभाग से 1, संस्कृति

विभाग से 1 शामिल है। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि सभी शासकीय कर्मचारी सदैव प्रशासन की सेवा करते हैं, उनके पूरे सेवाकाल की समाप्ति पर सहसम्मान विदाई हो इसके लिए प्रोजेक्ट वंदन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अब से किसी भी विभाग के कर्मचारी रिटायर होंगे, उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी।

HEALTH TOWN

DR. ABHIMANYU'S
AYURVEDA MULTISPECIALTY HOSPITAL
PAIN (PAINCLINIC) | PILES | PREGA | LYONIA | BAKEN

> वात रोग > पित्त के दर्द > पीत व कफ दर्द > स्थाविराण्डित > शिवाग्रेट के दर्द
> स्थाविराण्डित > गोलफ एक्को > प्रमेजब लोअर > रात्रीर ने जकड़न

कोहू, कर्न, संचयनितो के सच्चे प्रभाव दर्द का इलाज

9 सिटी सेंटर - कृष्णा टॉकीज के सामने, समता कॉलोनी रायपुर (छ.ग.) ☎ 9826446666
9 सेक्टर -7 कमल विलर, रायपुर (छ.ग.) ☎ 95224-66664, 62622-22003

Piles Care Clinic
Unit of Dr. Abhimanyu's Pain Relief Center
150 9001/2015 Certified Clinic

मानदुर कलेक्टर सभी कर्मचारियों का इलाज

किना चौराहा के बावलीर (पाइलर), फिदुरा (गमंदर) फिदर, गिलाडिडर पाइलर का

संजूर सगीन /क्षार सूत्र आयु आरोग्य की सुविधा

लेडिस डॉक्टर उपलब्ध

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130



खिलाड़ियों ने अनेक पदक जीता
महासमुंद। स्थानीय मां गायत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं दिव्या रंगारी, योजना रंगारी, राइमा दास, पलक पंचबुद्धे, स्वाती यादव ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट स्थान बनाते हुए गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज अनेक पदक अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान बनाने पर इन छात्राओं का चयन अन्तरराष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप मलेशिया के लिए चयनित हुए हैं, जहां अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के साथ नगर का नाम भी विश्व पटल पर अंकित किया है। इन खिलाड़ी बच्चों की प्रतिभा को निखारने जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन, सहायक जिला क्रीडा अधिकारी अंजलि बरमाल द्वारा उन्हें खेल छात्रवृत्ति के अंतर्गत संस्था की प्राचार्य विमला सागर को छात्राओं के लिए दस—दस हजार रुपए की चेक प्रदान करते हुए कहा कि ये होनहार खिलाड़ी बच्चे क्षेत्र और प्रदेश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। चयनित होने पर कोच शुभम तिवारी, मां गायत्री शिक्षण समिति की अध्यक्ष लगनी देवी सागर, जिला खेल अधिकारी मनोज धृतलहरे, नोडल प्राचार्य अमी रुफस सेजेस नयापारा, बीआरसीसी जागेश्वर सिन्हा, सागर स्कोर एकेडमी के संचालक केआर सागर, शाउमावि गढ़सिवनी प्राचार्य तुलेंद्र सागर, संकुल प्राचार्य सुखेंद्र द्विवेदी, सीआरसी मो शंख रसीद कुरेशी आदि ने हर्ष जताया है।

नपाध्यक्ष की पहल पर नागरिकों को अस्थाई प्याऊ से मिल रहा शुद्ध शीतल जल

हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

भीषण गर्मी व लू के प्रकोप के बीच पालिकाध्यक्ष निखिलकांत साहू की पहल पर पालिका द्वारा नागरिकों के लिए नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर जार वाला शुद्ध एवं ठंडा



पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी प्याऊ स्थापित किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू का दावा है कि प्रदेश में यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत नागरिकों को जार के माध्यम से

डीएलएड परीक्षा का उड़नदस्ता टीम ने किया निरीक्षण

सरायपाली। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र का उड़नदस्ता टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। आयोजित डीएलएड परीक्षा की निष्पक्षता और व्यवस्था को जांचने के उद्देश्य से निरीक्षण किया गया। टीम में मुख्य रूप से विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीसी पटेल एवं बीआरसी देवानंद नायक तथा सविता साहू शामिल थे। उड़नदस्ता टीम ने केंद्र में पहुंचकर चल रही परीक्षा की सुरक्षा, बैठक व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजामों का बारीकी से जायज लिया। केंद्र में दर्ज कुल 100 विद्यार्थियों में से 99 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित पाए गए। जबकि, 1 विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। परीक्षा केंद्र में पूरी शांतिपूर्ण, सुचारू और कड़े अनुशासन के बीच संचालित होती पाई गई। निरीक्षण के दौरान केंद्र के केंद्राध्यक्ष दिलीप कुमार नायक, सहायक केंद्राध्यक्ष मनोज पटेल एवं लिपिक कुलदीप सतपथी की उपस्थिति में उड़नदस्ता टीम ने केंद्र की पारदर्शी और व्यवस्थित परीक्षा संचालन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।

सीतापुर की घटना प्रशासनिक तानाशाही का प्रतीक, महासमुंद में भी किसानों के वर्षों पुराने मामले हैं लंबित : डॉ. चोपड़ा

हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने एक प्रेस विज्ञापित जारी कर सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और अपमान की कड़े शब्दों में निंदा की है। डॉ. चोपड़ा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में जो मनमर्जी और तानाशाही कांग्रेस के जमाने में चलती थी, वही दर्ा आज भी कायम है। इसके कारण आम जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही है, विशेषकर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही चरम पर है।

डॉ. चोपड़ा ने सीतापुर की घटना का हवाला देते हुए कहा कि विधायक का बहन सीमा धनकी अपने काम के लिए बोते 14 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही थी। तहसीलदार द्वारा उन्हें लगातार 14 दिनों तक घुमाया गया, जिससे उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक था। सामने आए वीडियो से साफ पता चलता है कि नायब तहसीलदार बातों को घुमा रहे हैं। जिस तहसीलदार को खुद यह नहीं पता कि कहां दस्तखत करना है और इसके लिए उसे अपने बाबू पर निर्भर रहना पड़ता है, वह तहसील का काम संभालने के लायक ही नहीं है।

डॉ. चोपड़ा ने शासन से अनुरोध किया है कि पुनः विचार करें और प्रकरण की गंभीरता से जांच करते हुए विधायक को राहत दिलाई जाए। और नायब तहसीलदार जो लगातार लोगों से दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायक रामकुमार टोप्पो के साथ है और पूरा संगठन सरकार से अनुरोध करता है कि प्रकरण की गहराई से जांच करके, इनके कारणों का, कि किस प्रकार से नायब तहसीलदार जो अनुचित व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण ये सारी घटनाएं जो हुई



जवाबदेही तोय हो सके। डॉ. चोपड़ा ने स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक रवैये को उजागर करते हुए कहा कि महासमुंद जिले में भी किसानों के



प्रदान नहीं कर पा रही है। सुशासन तिहार के शिविरों में बड़े-बड़े टेंट, माइक में लाखों रुपए फूँके जा रहे हैं, दूसरी ओर, निराश्रित जरूरतमंदों का पैसा रोका जा रहा

वर्षों पुराने राजस्व प्रकरण लंबित पड़े हैं, जिन्हें जानबूझकर नहीं निपटाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी खुद को कानून से भी ऊपर समझते लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल और डिजिटल क्रांति का जमाना है। राजस्व कार्यालय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीएम दौरे पर चले जाते हैं तो पक्षकारों (किसानों) को मोबाइल पर इसकी सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन, दफ्तरों में खाली बैठे बाबू भी पक्षकारों को कोई जानकारी नहीं देते। दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों और किसानों का हजारों रुपया और कीमती समय बर्बाद होता है। आम जनता के कागजात में

राजस्व विभाग के लोग त्रुटि करते हैं। टंकण त्रुटि या लिखने में त्रुटि करते हैं। और उसमें जब सुधार के लिए जनता को पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके कारण इनकी गलती को लेकर के आम जनता परेशान रहती है।

गलती ये अधिकारी, कर्मचारी खुद करते हैं और भुगतना पीड़ित आम जनता को पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके कारण इनकी गलती को लेकर के आम जनता परेशान रहती है। आने वाले ग्रामीणों और किसानों का तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीआईसी बैठक में होगी निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा

महासमुंद। नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि आगामी पीआईसी (प्रेसिडेंट इन कार्सिल)



बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह देखा जाएगा कि विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णयों में से कितनों पर अमल किया गया है तथा लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित निर्णयों की अद्यतन जानकारी एवं प्रगति प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत करें। जिन निर्णयों पर अब तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है, उनके संबंध में कारण एवं शीघ्र निराकरण की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक का उद्देश्य पीआईसी /परिषद के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों में गति लाना है। अध्यक्ष ने कहा कि पीआईसी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बुजुर्ग, दिव्यांगों, निराश्रितों को 5 माह से नहीं मिली पेंशन: आलोक शिविरों में नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान तो सुशासन तिहार क्यों

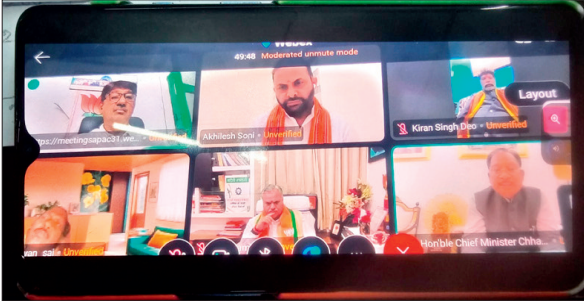
हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री आलोक चंद्राकर ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीबों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के प्रति असंवेदनशील हो गई है। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन पिछले 5 महीनों से हितग्राहियों को नहीं मिली है। एक तरफ भाजपा की साय सरकार पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार मना रही है, वहीं, दूसरी ओर जरूरतमंदों को महज 500 रुपए का पेंशन भी

हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के गौरवमयी 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली प्रगति पथ यात्रा और जनसंपर्क अभियानों को लेकर एक प्रदेश स्तरीय वरुंचुअल बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा यात्रा की तैयारियों और इसकी सफलता को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक को मुख्य रूप से भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जानदलपुर विधायक किरण सिंहदेव और प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय ने संबोधित किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रगति पथ यात्रा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी व महासमुंद के पूर्व



विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने बैठक की जानकारी देते हुए विज्ञापित जारी कर बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना है।

इस यात्रा के अंतर्गत प्रदेश के सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हैं वे सभी क्षेत्रों में जाकर

विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण करेंगे। साथ ही मीडिया के माध्यम से इन उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक किया जाएगा।

वरुंचुअल बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी डॉ. विमल चोपड़ा ने सांगठनिक मजबूती और यात्रा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से एक विशेष आग्रह किया। डॉ. चोपड़ा ने अनुरोध किया कि कैबिनेट के सभी मंत्रीगण स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए प्रदेश

के कम से कम एक या दो चिन्हित विकास स्थलों का दौरा करें। सर्वियों की उपस्थिति से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा और सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य सीधे जनता के समक्ष मजबूती से उजागर होंगे।

बैठक में यह संकल्प लिया गया कि प्रगति पथ यात्रा के साथ-साथ आने वाले सभी जनसंपर्क कार्यक्रमों को पूरी भव्यता और सफलतापूर्वक कराया जाएगा। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और छत्तीसगढ़ में साथ सरकार के सुशासन के संदेश को लेकर हर घर तक पहुंचेगा। इस वरुंचुअल बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य एवं संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी व जनसंपर्क अभियान के सभी प्रदेश के प्रमुख उपस्थित थे।

तेलीबांधा तालाब हमारी पहचान, तिरासत और गौरव का प्रतीक: तुषार महासमुंद

राष्ट्रीय तेली कर्मा सेना के संस्थापक व भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति सदस्य अशवंत तुषार साहू ने रायपुर नगर निगम व छत्तीसगढ़ शासन से विशेष मांग करते हुए कहा कि तेलीबांधा तालाब का इतिहास तैलिक वंशी साहू समाज की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक योगदान से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी पावन स्थल पर साहू समाज द्वारा प्रतिवर्ष 'हरेली उत्सव' का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों समाजजन सम्मिलित होकर अपनी संस्कृति और परंपराओं का उत्सव मनाते हैं। तुषार ने कहा कि हर्ष का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में पूर्व में भक्त माता कर्मा चौक एवं तेलीबांधा तालाब परिसर में भक्त माता कर्मा की प्रतिमा स्थापना की मांग समाज की ओर से प्रमुखता से रखी जा चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा इस मांग पर सकारात्मक आश्वासन भी प्रदान किया गया था। भक्त माता कर्मा त्याग, तपस्या, सेवा, नारी शक्ति और सामाजिक समरसता की प्रेरणा है। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ शासन व नगर निगम रायपुर से विनम्र मांग है कि तेलीबांधा तालाब जैसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल पर भक्त माता कर्मा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर तैलिकवंशी साहू समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए।

बंदरों के उत्पात से ग्रामीण हलाकान, कच्चे घरों को पहुंचा रहे नुकसान



नर्रा। मानसून सिर पर है। क्षेत्र के ग्रामीण इन दिनों भीषण गर्मी व तेज धूप के बीच अपनी छतों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन ग्रामीणों के आशियाने पर अब बंदरों की नजर पड़ गई है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह बंदर खपरेल की छत पर बैठे हैं और कवेलू खिखरे पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि

बंदरों के इस उत्पात के कारण उन्हें साल में कम से कम तीन-तीन बार अपने घरों की मरम्मत करानी पड़ती है। परेशानी सिर्फ बंदरों की उछल-कूद तक सीमित नहीं है। अब गांवों में न तो पारंपरिक काड़-पाटी और बता मिल रहे हैं, और न ही मिट्टी के खपरेल बनाने वाले कारीगर बचे हैं। ऐसे में टूटी छत को ढंकने के लिए

गरीब ग्रामीणों के पास अब पॉलीथिन और धान की पराली का ही एकमात्र सहारा बचा है। बंदर जंगलों में खाने पीने की चीजे नहीं होने से से गांवों की ओर रूख कर रहे हैं। गांवों में आसानी से भोजन की उपलब्धता है। जबकि गांवों में उन्हें बिना किसी बड़े खतरे के भरपेट भोजन मिल जाता है। बता दें कि पेटलों की ढाड़ियों

में खाने पीने के चीजे में सब्जियों में टमाटर, बैंगन, गोभी, मिंडी, बरबट्टी के अलावा जाम, इमली, कूंग के पास टंकी में रखे पानी उपलब्ध और रहने के लिए पेड़ भी है। किसानों को सब्जियों की रखवाली के लिए दिन भर सजग रहना पड़ता है। बंदर एक, दो नहीं बल्कि झुंडों में रहते हैं।

विडंबना: आदिवासी परिवार के साथ गाली-गलौज का मामला

24 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं

हरिभूमि न्यूज ►► पियौरा (ग्रामीण)

आदिवासी परिवार के साथ कथित

- एससी-एसटी एक्ट मामले में भाजपा नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जाति सूचक गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी एवं जमीन विवाद से जुड़े प्रकरण में भाजपा के प्रदेश



कार्रवाई नहीं होने से आदिवासी परिवार में भय का माहौल

पुलिस द्वारा एफआईआर किए जाने के 24 दिन बाद भी आरोपी दंपति की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल है। परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, और लगातार समझौते के लिए आदिवासी परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रदेश में आदिवासी नेता के मुख्यमंत्री होने और आरोपी के भाजपाई होने के कारण गिरफ्तारी नहीं होने पर सताथीशों का दोहरे चाल चरित्र उजागर हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन से तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दुलीकेशन साहू एवं किरण साहू ने गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका लगाई जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

कार्यसमिति सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेता दुलीकेशन साहू की अग्रिम जमानत याचिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज होने के 24 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना मामले में सत्ता का प्रभाव और राजनीतिक दबाव की चर्चा आम है।

जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण, किसानों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही उर्वरक

हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में किसानों के लिए खाद एवं उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा जिले की सभी सहकारी समितियों एवं विक्रय केंद्रों में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसानों को समय पर खेती कार्य के लिए आवश्यक उर्वरक मिल सके।

उपसंचालक कृषि एफआर कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वर्तमान में यूरिया 16,409 मीट्रिक टन, सुपर फास्फेट 8,881 मीट्रिक टन, पोटाश 2,207 मीट्रिक टन तथा डीएपी 6,476 मीट्रिक टन भंडारण किया गया है। वहीं अब तक किसानों को यूरिया 6,908 मीट्रिक टन, सुपर फास्फेट 2,939 मीट्रिक टन, पोटाश 343

मीट्रिक टन तथा डीएपी 1,823 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में खाद की कमी नहीं है तथा आवश्यकतानुसार भंडारण किया



गया है।किसानों की आवश्यकता के अनुसार निरंतर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा सभी विकासखंडों में खाद भंडारण एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर विनय

लंगेह ने सभी सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं को पीओएस मशीन के माध्यम से पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर ही खाद उपलब्ध कराया जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को पारंपरिक यूरिया के साथ-साथ नैनो यूरिया के उपयोग के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार नैनो यूरिया के प्रयोग से कम मात्रा में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं।